फूड मिनिस्ट्री ने दिया चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने का प्रपोजल

[ईटी ब्यूरो & पीटीआई | पुणे & नई दिल्ली]

फूड मिनिस्ट्री ने सस्ती चीनी के इंपोर्ट पर रोक लगाने, होलसेल प्राइस में गिरावट थामने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 100 पर्सेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। 2017-18 सीजन (अक्टूबर से सितंबर) में अनुमान से 60 लाख ज्यादा चीनी उत्पादन होने के अनुमान पर होलसेल प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन से नीचे आ गया है।

रिटेल मार्केट में चीनी 40 से 42 रुपये प्रति किलो के रेट से मिल रही है। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स जल्दी कोई नीतिगत फैसला होने की उम्मीद कर रहे हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गौरव गोयल ने कहा, 'दो साल चीनी का एक्सपोर्ट किए जाने की जरूरत है।' सूत्रों ने बताया कि घरेलू गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए चीनी पर लागू इंपोर्ट ड्यूटी को 50 पर्सेंट से बढ़ाकर 100 पर्सेंट करने की सिफारिश फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजी गई है। उन्होंने बताया कि इस बाबत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। शुगर इंडस्ट्री बॉडी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) और NFCSF ने मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है क्योंकि प्रॉडक्शन में बढ़ोतरी की संभावना पर चीनी का एक्स फैक्टरी प्राइस 29.50-30 रुपये प्रति किलो से नीचे आ गया है। देश में 2017-18 के मौजूदा सीजन (अक्टूबर से सितंबर) में चीनी उत्पादन उम्मीद से चार पर्सेंट ज्यादा बढ़कर 2.61 करोड़ टन होने का अनुमान दिया गया है। 2016-17 के शुगर सीजन में 2.03 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

- 2017-18 के मौजूदा सीजन (अक्टूबर से सितंबर) में चीनी उत्पादन उम्मीद से 4% बढ़कर 2.61 करोड़ टन होने का अनुमान
- इस साल देश में चीनी की खपत 2.5 करोड़ टन रहने का अनुमान, 2016-17 के सीजन में 2.03 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था

इस साल देश में चीनी की खपत 2.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चीनी का उत्पादन उम्मीद से ज्यादा रहने के अनुमान से महाराष्ट्र के किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीनी के दाम में गिरावट आने की वजह से उनको गन्ने के लिए कम प्राइस ऑफर किया जा रहा है।इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गौरव गोयल ने कहा, 'सरकार जानती है कि चीनी के दाम में आ रही गिरावट से गन्ना किसानों का पेमेंट बकाया बढ़ रहा है। इस सीजन में चीनी का उत्पादन 2.61 करोड़ टन के अनुमान से ज्यादा रह सकता है। हालांकि हालात की सही तस्वीर अगले महीने मिलेगी जब ISMA हालात का दोबारा जायजा लेगी।'महाराष्ट्र के शोलापुर और पुणे क्षेत्र में गन्ने के बकाया पेमेंट में कटौती पहले ही शुरू हो चुकी है।

पिछले हफ्ते कोल्हापुर इलाके के चीनी मिलों ने गन्ने के पेमेंट में 500-600 रुपये प्रति क्विंटल की कमी करने का फैसला किया। ये मिलें अब गन्ना किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से पहली किस्त का पेमेंट करेंगी। ISMA के वाइस प्रेसिडेंट रोहित पवार ने कहा, 'मिलें चीनी के दाम में कमी आने और बैंक लेंडिंग में कमी के चलते गन्ने का भुगतान घटा दिया है।'